जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 171 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 26 अप्रैल, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारत ने अपने ''रैस्पाँस'' से पाकिस्तान के गले के फंदे को और टाइट किया

वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति पहले ही बड़ी नाज़ुक थी, महँगाई 2025 के प्रारम्भ में 20.8 प्रतिशत हो गई थी, पाकिस्तानी रूपया, अमेरिकी डॉलर की तुलना में गत दो वर्ष में 30 प्रतिशत वैल्यू खो चुका है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रेल। पहलगाम में हुआ नरसंहार, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों को एक क्रूर आतंकी हमले में मौत के घाट उतार दिया गया, उपमहाद्वीप की पहले से ही असहज शांति में एक गंभीर मोड़ बन गया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान-स्थित जिहादी नेटवर्क को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कई कड़े दंडात्मक कदम उठाए हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद की पहले से ही कमजोर नींव को हिला दिया है। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, व्यापार मार्गों को अचानक बंद करना और वीज़ा प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देना, इन सबने पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक रूप से घेर लिया है।

एक ऐसा देश, जो पहले ही बेलगाम महंगाई, भारी विदेशी कर्ज और लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, उसके लिए भारत की यह प्रतिक्रिया एक करारी चोट है। संदेश स्पष्ट है: इसकी कीमत चुकानी होगी-और वह कीमत असहनीय होगी। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, और उसकी हुकूमत को घरेलू असंतोष और आर्थिक पतन स्पष्ट नज़र आ रहा है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही नाजुक हालत में थी, अब टूटने की कगार पर है। देश गंभीर महंगाई से जूझ रहा है-2025 की शुरुआत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे जीवन, यापन की लागत, खासकर कामकाजी और मध्यम वर्ग के लिए, असहनीय हो गई है। पाकिस्तानी रुपया पिछले दो वर्षों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है, जिससे आयात महंगा हो गया है और रोज़मर्रा की चीज़ें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पाकिस्तान का विदेशों से लिया हुआ ऋण जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा हो गया है।
- भारत द्वारा ''इंडस वॉटर ट्रीटी'' के तहत पाकिस्तान को पानी छोड़ने से मना करने से पाकिस्तान कांप गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कृषि उत्पाद, उसकी जीडीपी का चौथाई हिस्सा है तथा 40 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है।
- पानी बंद होने से फूड सप्लाई प्रभावित होगी तथा इससे जो इकोनॉमिक नुकसान होगा वह जीडीपी के दो प्रतिशत के बराबर होगा।
- ट्रेड रूट्स बंद करने से लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान होगा, पड़ोसी देश से व्यापार तब तक के लिए बंद हो जायेगा, जब तक कि पाकिस्तान आयात के लिए वैकल्पिक रास्ते व स्रोत नहीं ढूंढ़ लेता।
- इस इकोनॉमिक ''डाउन टर्न'' के कारण विदेशी मुद्रा का निवेश, जो पहले ही घट रहा था, और घट जायेगा और इकॉनमी का ''रिवाइवल'' और कठिन होगा।

नाबालिग छात्रा का अपहरण-दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल की सजा

जयपुर, 25 अप्रैल। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अजब सिंह उर्फ अमित को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल द्वितीय ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र की पीड़िता को उसके माता-पिता की मंजूरी के बिना कथित विवाह व संभोग करने के आशय से बहलाकर कई जगह पर ले गया। उसने कई जगहों पर पीड़िता के साथ संबंध बनाए। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

- नाबालिग छात्रा एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी व अभियुक्त वहाँ पढ़ाता था।

अभियोजन पक्ष की ओर से मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में 6 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी निजी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ती है और अभियुक्त भी वहां पढ़ाता है। उसकी बेटी 5 अक्टूबर को स्कूल से दोपहर दो बजे आ गई थी। उसने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत अब नये हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्ट्स पर भी काम शुरु कर रहा है

यह हाइड्रो पॉवर अब तक लटके हुए थे, पाकिस्तान द्वारा इंडस वॉटर ट्रीटी को आधार बनाकर लगातार आपत्ति जताने के कारण

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रेल। संक्षिप्त अवधि, मध्यम अवधि तथा दीघकालीन योजनाओं पर काम करते हुये तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुये कि पाकिस्तान को ''पानी की एक बूँद'' नहीं मिले, भारत ने सिन्धु जल समझौते (इन्डस वॉटर्स ट्रीटी) को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा भी, भारत कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहा है, जिनमें उन हाइड्रोपावर प्रोजेक्टों के काम में तेजी लाना शामिल है, जिन पर पाकिस्तान ने, ट्रीटी का हवाला देते हुये, आपत्ति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि भारत, पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा उपलब्ध कराना बंद करने की योजना भी बना रहा है। जाहिर है, इस प्रकार के डेटा बाढ़ और सूखा प्रबन्धन के लिये पड़ोसी देश के लिये अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने कुछ और कदम उठाने का भी निर्णय लिया है, जैसे बाँधों की डी-सिल्टिंग, नदियों के पानी का रास्ता एवं दिशा बदलने के तरीकों तथा नये बाँध बनाने के विकल्प।

- साथ ही अब भारत ने पाकिस्तान को इन नदियों में पानी की आवक, बरसात के आंकड़े आदि देना भी बंद कर दिया है। ये हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान के लिये बहुत अहमियत रखता है, बाढ़ व सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए।
- भारत सरकार इन नदियों पर बने बाँधों पर ''डीसिल्टिंग'' का काम भी शुरु कर रही है तथा नदियों का पानी डाइवर्ट करने के तरीकों, जैसे नये बाँध बनाने की योजनाओं, पर कार्यवाही शुरु कर दी है।
- भारत इस बात की कोशिश में है कि पाँचों नदियों, व्यास, रावी, सतलज, चेनाब, इंडस व झेलम, का पानी पाकिस्तान न पहुँचे।

भारत और पाकिस्तान ने ''सिन्धु जल समझौता'' पर 1960 में हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते पर, विश्व बैंक अतिरिक्त हस्ताक्षरकर्ता था। इस समझौते में सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच बराबर बाँटने की कोशिश की गई थी। समझौते के तहत, तीन पूर्वी नदियों- व्यास, रावी और सतलज का पानी भारत को तथा तीन पश्चिमी नदियों - चिनाब, सिन्धु और झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।

शुक्रवार को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक मीटिंग में, सर्वसम्मति से यह बात उभर कर आई कि नई दिल्ली को उन सभी चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार रहना चाहिये,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सावरकर के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति की

सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी भी राहुल गाधी को दी, कि अगर ऐसी टिप्पणी दोहराई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा सुप्रीम कोर्ट और इस मुतल्लिक सम्मन भी जारी होंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रेल। वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी के लिये शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी खिंचाई की, लेकिन सम्मनों पर स्टे दे दिया।

अदालत ने गांधी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस प्रकार के बयान दिये तो अदालत अपनी ओर से ही कार्यवाही शुरु कर देगी।

अदालत ने राहुल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति की कि विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे तथा अंग्रेज उन्हें पेन्शन देते थे।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता तथा मनमोहन की बैंच ने कहा कि इस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है तथा अगर उन्होंने आगे भी ऐसे ही बयान दिये तो अदालत स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरु कर देगी। तथापि, बैंच ने उन सम्मनों पर स्टे दे दिया, जो विवादास्पद बयानों को लेकर उनके खिलाफ चल रहे एक क्रिमिनल केस में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किये थे।

- कोर्ट ने राहुल गांधी को स्मरण कराया, कि देश की पूर्व प्र.मंत्री व उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ की थी।
- राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में कहा था, कि वे ब्रिटिश सरकार के नौकर थे तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन भी मिलती थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''आपने कानून का एक अच्छा बिन्दु प्रस्तुत किया तथा आपको स्टे मिल जायेगा। लेकिन उनके द्वारा आगे दिये गये ऐसा किसी बयान का स्वत: संज्ञान ले लिया जायेगा। स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ इस तरह पेश आयें? नोटिस जारी कीजिये। ऑर्डर पर स्टे (दिया जाता है)।

स्टे देते हुये, बैंच ने यह बात विशेषरुप से कही कि राहुल गांधी की दादी तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को लिखे पत्रों में उनकी प्रशंसा की थी।

राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मुखातिब होते हुये, अदालत ने कहा, ''क्या उन्हें (राहुल) मालूम है कि महात्मा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक नागरिकों को जारी वीज़ा 27 अप्रैल से रद्द

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा को छोकर अन्य वीज़ा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।

केंदीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक , राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा रद्द नहीं किए गए हैं। मेडिकल वीजा को भी कुछ राहत दी गई है और ये 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।

- दीर्घकालिक, राजनयिक व अधिकारिक वीज़ा कायम रहेंगे और मैडिकल वीज़ा को भी राहत दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा अन्य सभी श्रेणियों में जारी वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम तीन दशक से आतंकवादियों को फण्ड कर रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं'

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने इंगलैंड की स्काई न्यूज़ को दिये गये इंटरव्यू में स्वीकार किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका देश लम्बे समय से आतंकी समूहों को प्रशिक्षण व पैसा दे रहा हैं, यह कोई साधारण काम नहीं है। इस बयान ने दशकों के इन्कार का पर्दाफाश कर वह सच सामने ला दिया है, जिसके लिए भारत लम्बे समय से कह रहा है, बल्कि इससे वह गंदा खेल भी उजागर होता है। कई दशकों से अमेरिका खेल रहा है, उन सरकारों को अस्थिर करने या गिराने के लिए जो अमेरिका के निर्देश को चुनौती देती है।

आसिफ ने यूके के स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा, ''हम पिछले लगभग तीन दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम के लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है।'' यह इंटरव्यू पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए

- रक्षा मंत्री ने कहा, वे यह सब अमेरिका व पश्चिमी देशों, जैसे ब्रिटेन के लिए एक सुनियोजित नीति के तहत कर रहे थे।
- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत कई दशकों से पाकिस्तान के इन आतंकवादी समर्थक कृत्यों के बारे में हल्ला करता रहा है, पर, पाकिस्तान इससे इन्कार करता रहा है।

तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है। जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों बाद हुआ यह सबसे घातक हमला था, जिसमें 26 लोग मारे गए व अधिकांश पर्यटक थे।

उन्होंने यह बात तब कही, जब उनसे पाकिस्तान की आतंकियों को फंडिंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने आगे कहा कि देश के पिछले निर्णय ''गलती'' थे जिनसे दीर्घकालिक नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा, ''अगर हमने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद युद्ध में भाग नहीं लिया होता तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता।''

उन्होंने वैश्विक शक्तियों पर उंगली उठाई।

उन्होंने कहा, ''बड़ी ताकतों के लिए पाकिस्तान को दोष देना सुविधाजनक था जिसने ''उनके पक्ष में'' 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ा। आज वे सभी आतंकवादी वॉशिंगटन में स्वागत-सत्कार पा रहे हैं।''

आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने स्वयं सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान आतंकियों को ''प्रॉक्सी'' के रूप में इस्तेमाल किया।

भारत ने बार-बार पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को शरण देने और समर्थन देने का आरोप लगाया है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में।

द रैजिस्टैंस फ्रंट (टीआरएफ), जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है, ने पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ली है।

इस हमले के बाद भारत ने कठोर कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि जल प्रवाह को रोका गया, तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, और उसने भी भारत के साथ व्यापार बंद करने और भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसे कदम उठाए हैं।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तनाव बढ़ने की चेतावनी दी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी कश्मीर पहुँचे

श्रीनगर, 25 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में बढ़ ते तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को कश्मीर पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना प्रमुख के आगमन के तुरंत बाद उन्हें सेना के श्रीनगर स्थित 15 कोर कमांडर ने सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम के बैसरन मैदान में हमले के मद्देनजर आतंकवाद विरोधी

- वे पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे।

अभियानों के बारे में जानकारी दी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।

सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में भी जानकारी दी गई। सेना प्रमुख के श्रीनगर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो दिन में ही 1200 से ज्यादा ''कैन्सलेशन'' आए, कश्मीर के होटल व टूर ऑपरेटर्स के पास

कश्मीर के ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोग, इस बार कश्मीर का ''बैस्ट सीज़न'' होने की आशा कर रहे थे, पर, पहलगाम के बाद सब आशाएं धूमिल हो गईं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले ने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को आहत किया है, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था के हृदय, यानी इसके पर्यटन उद्योग को भी तोड़ कर रख दिया है। जिस समय कश्मीर घाटी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर अपनी खोई जगह पुन: हासिल करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय हुए इस नरसंहार ने इस रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे टूरिस्ट सीज़न पर ब्रेक लगा दिए।

होटल खाली हो रहे हैं। बुकिंग कैंसल हो रही हैं और कश्मीर के होटल उद्योग में जो उत्साह और उल्लास का माहौल था, वहाँ अब निराशा व अवसाद नज़र आ रहा है। इस हिंसा का असर सिर्फ राजनैतिक और सैन्य क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका असर श्रीनगर के बाज़ारों में दिख रहा है, डल झील के शिकारों और गुलमर्ग और पहलगाम के होटलों पर दिख रहा है, जो कुछ समय पहले तक पर्यटकों से गुलज़ार थे। कश्मीर के लिए आतंकवाद की कीमत है, कैंसल होती ट्रिप्स तथा रोजगार व आजीविका का छिन जाना।

जम्मू कश्मीर के टूर ऑपरेटर्स व होटल वालों ने बताया है कि भारी मात्रा में बुकिंग कैंसल हुई हैं और भविष्य में बुकिंग की संभावना भी ठंडे बस्ते में हैं। अब तक 800 से 1200 बुकिंग्स कैंसल

- जैसा कि विदित ही है, पर्यटन का जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में सात प्रतिशत का योगदान होता है तथा इस उद्योग से बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।
- टूरिस्ट इण्डस्ट्री को केवल बुकिंग्स व आमदनी का ही नुकसान नहीं है, कश्मीर के टूरिज़्म की छवि आहत हुई है, जिसका नुकसान पैसों-टकों से नहीं आंका जा सकता।

हो गई हैं और अगर सुरक्षा संबंधी भय का समाधान नहीं किया गया तो यह संख्या और बढ़ेगी।

जम्मू के एक ट्रैवल एजेंट रविंदर सिंह ने बताया कि ''मार्च और अप्रैल की उसकी 50 प्रतिशत बुकिंग्स रद्द हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश तो आतंकी घटना के कुछ ही घंटों में रद्द हो गई थीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि कई सालों बाद इस बार बैस्ट टूरिस्ट सीज़न होने जा रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि हम फिर वहीं पहुँच गए हैं।''

श्रीनगर के होटल कैसर के मालिक शेख उमर ने भी कहा कि उनके होटल में भी काफी बुकिंग्स कैंसल हुई हैं। पर लचीलापन भी है। ''हमें अभी भी मुम्बई और बैंगलुरू जैसे शहरों से फोन आ रहे है। लोग आना चाहते हैं, पर उन्हें सुरक्षा का भरोसा चाहिए।'' समूचा उद्योग जगत चिंतित है और इस कृत्य की आलोचना कर रहा है। जम्मू-कश्मीर होटलायर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया ने साफ कहा कि ''यह स्थिति कश्मीरियों को स्वीकार्य नहीं है। इस घटना के पीछे जो लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। यह स्वीकार्य नहीं है, लोग मारे जाते और अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है।'' उनका बयान स्थानीय व्यवसायियों में बढ़ती निराशा और क्षोभ को दर्शाता है, जिसने आतंकवाद के दिनों में भारी संघर्ष किया है।

ट्रैवल एजेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष रऊफ ट्राम्बो ने कहा कि ''हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं और शांति स्थापना के लिए सरकार को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा देते है। पर्यटकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।'' एसोसिएशन नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है।

जम्मू कश्मीर की जीडीपी का 7 प्रतिशत पर्यटन उद्योग है और 20 लाख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. कस्तूरीरंगन का निधन

बेंगलुरु,25 अप्रैल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष , पूर्व सांसद एवं प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन का शुक्रवार का बेंगलुरु में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। डॉ. कस्तूरीरंगन का निधन आज सुबह 10:43 बजे हुआ।

- प्रधानमंत्री मोदी ने 84 वर्षीय डॉ. कस्तूरीरंगन के निधन पर शोक जताया तथा कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में उनके योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा।

उनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआर आई) में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)